Date: 21 **जुलाई** 2023

न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / अर्थव्यवस्था

संदर्भ-

- राजस्थान ने राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक, 2023 **पेश किया**।

विधेयक के बारे मे

- इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। इस विधेयक के तहत 15 दिन के भीतर रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
- इस दौरान अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर यदि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो, वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- **विधेयक में तीन व्यापक श्रेणियां हैं:** न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार।
- **न्यूनतम गारंटीकृत आय:** राज्य के प्रत्येक वयस्क नागरिक को **शहरी क्षेत्रों के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से** वर्ष में 125 दिनों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी गई है।
- **गारंटीकृत रोजगार:** रोजगार का अधिकार कहता है कि शहरी या ग्रामीण रोजगार योजनाओं में काम करने के बाद, **न्यूनतम मजदूरी का भुगतान "साप्ताहिक या किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं" किया जाना चाहिए।**"
- **गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन:** वृद्धावस्था / विशेष रूप से सक्षम / विधवा / एकल महिला **की श्रेणी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति** निर्धारित पात्रता के साथ पेंशन का हकदार होगा।
- यह दो किस्तों में आधार दर से बढ़ेगा – जुलाई में 5 प्रतिशत और 2024-2025 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जनवरी में 10 प्रतिशत।
- **कार्यान्वयन: राज्य** अधिनियम को लागू करने के लिए **एक कार्यक्रम अधिकारी को नामित करेगा** – ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास **अधिकारी के पद से नीचे नहीं** और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय का **एक** कार्यकारी अधिकारी।
- कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि **कार्य स्थल पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जॉब कार्ड पंजीकृत** पांच किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

- यदि कार्यक्रम अधिकारी **आवेदन की प्राप्ति से** 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदक **साप्ताहिक आधार पर** बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

अर्थ-

- कानून उन लोगों के लिए रोजगार गारंटी को जोड़ता है जो [ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में] काम कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन – जिससे सभी के लिए न्यूनतम **कानूनी आय गारंटी सुनिश्चित होती है।**
- कई अन्य राज्यों ने भी हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं , लेकिन केवल कार्यकारी आदेश के माध्यम से। **यह पहली बार है जब शहरी रोजगार गारंटी योजना को विधायी समर्थन मिलेगा**।
- यह भी पहली बार है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक कानूनी गारंटी बन जाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पात्रता सूचकांक की मांग में एक कानूनी रूप से जानी जाएगी।

चुनौतिया-

- **राज्य पर वित्तीय बोझ:** इस योजना के लिए प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा , जो समय के साथ बढ़ सकता है जो राज्य पर अतिरिक्त बोझ पैदा कर सकता है।
- **योजना का लक्षित कार्यान्वयन: लक्षित** समूह को लाभान्वित करने के तरीके से योजना का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है।

आगे का रास्ता

- संविधान की मूल भावना के अनुसार , प्रत्येक व्यक्ति **को सम्मान के साथ जीने का अधिकार** है और इस योजना में राज्य भर के करोड़ों कमजोर परिवारों के लिए न्यूनतम आय गारंटी प्रदान करने का एक अच्छा इरादा है।

स्रोत: IE

Rajiv Pandey

नाटो का शिखर सम्मेलन

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संगठन

संदर्भ-

- हाल ही में , सदस्यों देशों के बीच मतभेद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विरोध के बीच नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विनियस में संपन्न हुआ।

हाल के शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें–

- लक्ष्य एक समझौते पर पहुंचना था कि स्वीडन गठबंधन में शामिल हो सकता है – जिसे तुर्की ने अवरुद्ध कर दिया था – और यूक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत करने के लिए।

- इन दोनों लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया।। फिर भी , एक मुद्दा जो विनियस शिखर सम्मेलन पर छाया हुआ था, वह गठबंधन में यूक्रेन की सदस्यता का वादा था, जिस पर कोई स्पष्टता या समय सीमा नहीं थी।
- नाटो की नई योजनाओं में वायु और नौसेना क्षमताओं के साथ 300,000 सैनिकों की सेना को बनाए रखना शामिल है, जबकि एक मजबूत औद्योगिक आधार के महत्व पर जोर दिया गया है , जिससे रक्षा उत्पादन कार्य योजना का समर्थन किया जा सकता है।
- नाटो शिखर सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ-साथ क्वाड देशों के लिए जगह के विस्तार के साथ हिंद-प्रशांत में विकास यूरो-अटलांटिक सुरक्षा के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है।

अमेरिका का रुख-

- शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के भाषण ने गठबंधन के साथ-साथ यूक्रेन को अटूट समर्थन दिया।

चुनौती-

- सैन्य गुट ने 15 बार चीन का उल्लेख करते हुए कहा कि "चीन की घोषित महत्वाकांक्षाएं और नीतियां हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती हैं"
- रूस ने शिखर सम्मेलन के दौरान कीव पर ड्रोन हमला किया, जो नाटो के संभावित विस्तार को अनदेखा करता है।
- यह मुकाबला यूरेशियन सुरक्षा के भविष्य को निर्धारित करने की संभावना रखता है।

भारत के लिए निहितार्थ-

- हाल के वर्षों में, भारत का नाटो के साथ सीमित जुड़ाव रहा है, ज्यादातर राजनीतिक संवाद के रूप में।
- भारत ने नाटो के नवीनतम विस्तार पर रणनीतिक रूप से चुप्पी साधी है। लेकिन उसे उन परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए जहां समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे का रास्ता-

- रूस द्वारा किसी भी रणनीतिक हमले का मुकाबला करने के लिए नाटो तैयार है।
- निरंतर आर्थिक संकट है और नेताओं ने यूक्रेन से अधिक से अधिक हथियारों और अन्य सैन्य समर्थन की मांग को पूरा करने का वादा किया है।
- नाटो के नेतृत्व में नए यूरोपीय सुरक्षा ढांचे और रूस द्वारा प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर भारत की वैश्विक भूमिका की जांच की जाएगी।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)-

- यह 1949 में स्थापित किया गया था और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देशों का एक समूह है जो अपने सदस्यों के लोगों और क्षेत्र की रक्षा के लिए जाना जाता है।
    - स्वीडन को **नाटो सदस्यों के रूप में मंजूरी** देना यह संकेत देता है कि अप्रैल 1949 में हस्ताक्षरित वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 10 कहा गया है कि सदस्य देश अन्य यूरोपीय देशों को नाटो का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।
- यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है , जिसका अर्थ है कि यदि एक नाटो सहयोगी पर हमला किया जाता है , तो सभी नाटो सहयोगियों पर हमला माना जाएगा । उदाहरण के लिए , जब आतंकवादियों ने 9/11 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया, तो सभी नाटो सहयोगी अमेरिका के साथ खड़े थे।
- **ओपन डोर पॉलिसी नाटो का एक संस्थापक सिद्धांत है** । इसका मतलब यह है कि यूरोप का कोई भी देश नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है यदि वह सदस्यता के मानकों और दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है, गठबंधन की सुरक्षा में योगदान देता है , और नाटो के स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन के मूल्यों को साझा करता है।

"नाटो प्लस"

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) प्लस ' (वर्तमान में नाटो प्लस 5) एक सुरक्षा व्यवस्था है , जो रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाटो और पांच देशों- ऑस्ट्रेलिया , न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल व दक्षिण कोरिया को एक साथ लाती है।
- दिलचस्प बात यह है कि 'नाटो प्लस' शब्द नाटो के भीतर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त या स्थापित अवधारणा नहीं है , लेकिन गठबंधन के संभावित विस्तार के बारे में चर्चा और बहस में इसका उपयोग किया गया है।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com